सेंट्रल नेशनल बैंक लिमिटेड

बनाम

युनाइटेड इंड्राटियल बैंक लिमिटेड

[बी.के. मुखर्जीया, भगवती एवं जगन्नाधदास, न्यायाधीश]

भारतीय माल विक्रय अधिनियम (वर्ष 1930 का तृतीय), धारा 30(2)- भारतीय संविदा अधिनियम (वर्ष 1872 का नौवा), धारा 13, 14- माल विक्रय का करार- क्रेता द्वारा मूल्य का भुगतान किए बिना कपटतापूर्वक कब्जा प्राप्त करना- क्रेता के बोनाफाइट खरीददार के अधिकार- सहमति का अर्थ।

धारा 30 (2) भारतीय माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत शब्द "सम्मति" का अर्थ है "एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होना" जैसा कि धारा 13 भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित किया गया है और इसका अर्थ धारा 14 में परिभाषित "स्वतंत्र सम्मति" नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल बैचने के लिए सहमत होने के पश्चात कब्जा प्राप्त करना कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के बावजूद, अन्यथा कपट ऐसा हो जो सम्मति को पूरी तरह से बाधित कर दे, धारा 30(2) माल विक्रय अधिनियम के अर्थ के अधीन "विक्रेता की सम्मति से" कब्जा प्राप्त करना होगा।

यह तथ्य कि उस व्यक्ति द्वारा कब्जा कपट या छलपूर्वक प्राप्त किया गया है, जो उसे आपराधिक दायित्व के लिए जिम्मेदार बताता है, इस सिद्धांत के लागू होने में कोई भेद नहीं करता है।

ए कुछ शेयर बी को बैचने के लिए सहमत होता है और शेयर प्रमाण पत्र व निरंक हस्तांतरण विलेख प्रतिवादी बैंक को बी को मूल्य प्राप्त करने के पश्चात देने के लिए भेजता है। बैंक अपने एक कर्मचारी को उक्त दस्तावेजात के साथ बी के कार्यालय में भेजता है। कर्मचारी ने उक्त दस्तावेजात मेज पर रखे और बी को उन्हें जांचने की

स्वीकृति दी परंतु उक्त दस्तावेज बी को देने से पूर्व मूल्य का भुगतान करने के लिए कहा। बी ने उक्त दस्तावेजात के साथ अपने कार्यालय को यह कहते हुए छाेड़ा कि वह पैसे लेने के लिए जा रहा है परंतु वह गायब हो गया और तदोपंरात उन्हें वादी के पास गिरवी रख दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी परिस्थितियों में बी ने ए की सम्मति के बिना शेयर का कब्जा प्राप्त किया है तथा वादी को प्रतिवादी बैंक या ए के विरुद्ध कोई स्वामित्व नहीं मिलता है।

फोक्स बनाम किंग (1923) 1 केबी 282 और लेख बनाम सिमंस (1926) 02 केबी 51 और पियरसन बनाम रोज (1950) 02 ऑल इआर 1027 पर निर्भर किया गया।

काह्न बनाम पोकेट्स ब्रिस्टल चैनल स्टीम पोकेट् कम्पनी ***(1899) 01*** *क्यूबी* ***643,*** *ऑपनहाइमर बनाम फ्रेजर* ***(1907) 02*** *केबी* ***50*** *पर टिप्पणी की गई।*

कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टी की गई।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल अपील संख्या 32/1953

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा अपने सामान्य मूल दीवानी क्षेत्राधिकारी के तहत दिनांक 21 मार्च, 1950 को मूल वाद संख्या 1112/1946 में पारित मूल डिक्री के खिलाफ अपील में कलकत्ता उच्च न्यायालय (हैरिस मुख्य न्यायाधीश और बनर्जी न्यायाधीश) के 12 मार्च, 1951 के निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ता की ओर से पी.सी. मलिक और ए.के दत्त।

प्रतिवादी की ओर से शंकर बनर्जी (बी. दास और एसएन मुखर्जीया, उनके साथ)।

26 नवंबर, 1953। न्यायालय का फैसला मुखर्जीया न्यायाधीश द्वारा दिया गया था।

यह अपील कलकत्ता उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के 12 मार्च, 1951 के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उन्हाेंने उसी अदालत के वाद संख्या 1112/1946 में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले को अपील में उलट दिया था।

वाद, जिससे यह अपील उत्पन्न होती है, सेंट्रल नेशनल बैंक लिमिटेड, हमारे समक्ष अपीलकर्ता, द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में, एक घोषणा के लिए शुरू किया गया था कि बैंक ने दो कम्पनियों इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल लिमिटेड के दो ब्लॉक के संबंध में गिरवीदार के अधिकार हासिल कर लिए हैं तथा वह गिरवी माल के प्रवर्तन में शेयर बेचने का हकदार था। इन शेयरों पर कब्जे की वसूली के लिए और प्रतिवादी बैंक द्वारा इसके स्वामित्व को गलत तरीके से अस्वीकार करने के कारण वादी को हुए नुकसान के लिए भी दावा किया गया था।

जिन शेयरों के संबंध में विवाद है, उनकी संख्या 800 है और यह स्वीकृत है कि वे वाद में प्रतिवादी नंबर 2, राधिका मोहन भुइया की संपत्ति थे। फरवरी, 1946 में किसी समय, भुइया इन शेयरों को द्विजेंद्र नाथ मुखर्जी को 38,562.80 रुपये की कीमत पर बेचने पर सहमत हुए। दिनांक 14 फरवरी, 1946 को, भुइया ने इन शेयरों को संबंधित हस्तांतरण विलेखों के साथ प्रतिवादी बैंक को इस निर्देश के साथ भेजा कि ऊपर बताई गई संपूर्ण प्रतिफल राशि के भुगतान के बदले शेयर प्रमाणपत्र और हस्तांतरण विलेख क्रेता को सौंप दिए जाएं। इसके बाद 18 फरवरी को प्रतिवादी बैंक ने अपने एक अधिकारी, नीलकृष्ण पॉल को निर्देश दिया कि वह मुखर्जी से उनके कार्यालय में मिलें और उनसे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हस्ताक्षरित 38,562.80 रुपये का भुगतान आदेश प्राप्त करने के बाद उन्हें शेयर सौंप दें। इस निर्देश के अनुसार, पॉल मुखर्जी के कार्यालय गए और सुबह लगभग 11 बजे उन्हें उनके कार्यालय में मिले। मुखर्जी ने

शेयरों की मांग की लेकिन पॉल ने उन्हें तब तक शेयर प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया जब तक कि भुगतान आदेश नहीं दिया जाए। मुखर्जी ने तब कहा कि वह खुद को संतुष्ट करने के लिए शेयरों और हस्तांतरण विलेख पर एक नजर डालना चाहते थे कि वे बिल्कुल सही थे। इसके बाद पॉल ने शेयर और हस्तांतरण विलेख को मेज पर रख दिया। मुखर्जी ने एक के बाद एक शेयर प्रमाणपत्रों की जांच की और जब वह शेयर प्रमाणपत्रों और बैंक हस्तांतरण विलेख के साथ कार्यालय छोड़ने वाले थे, तो पॉल ने आपत्ति जताई और उनसे भुगतान आदेश दिए बिना नहीं जाने के लिए कहा। मुखर्जी ने तब पॉल से कहा: "मैं भुगतान आदेश लेने के लिए बाहर जा रहा हूं; यह तैयार है। आप अपनी सीट पर बैठें; मैं आ रहा हूं।" इन शब्दों के साथ मुखर्जी अपने कार्यालय से बाहर चले गए और उसके बाद वापस नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सीधे वादी बैंक के कार्यालय में गया और एक करार के संदर्भ में, जो पहले उनके बीच हुआ था, के बदले 29,000 रुपये की अग्रिम राशि लेकर शेयर उसके पास गिरवी रख दिये। सम्पूर्ण घटना का सार यह है कि मुखर्जी ने 100/- रुपये का एक चेक दिया जिसके साथ उसका खाता पहली बार वादी बैंक में खोला गया था और इस चालू खाते पर बैंक अधिविकर्ष के माध्यम से मुखर्जी को 29,000 रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी। मुखर्जी ने वादी के पक्ष में उक्त राशि के लिए एक वचन पत्र भी निष्पादित किया। यह पक्षकारों का सामान्य मामला है कि मुखर्जी के बारे में तब से नहीं सुना गया है और उनका वर्तमान पता अज्ञात है। अब प्रतिवादी के अधिकारी पॉल पर आते हैं, जिसने मुखर्जी की व्यर्थ प्रतीक्षा करने के बाद अन्य कोई विकल्प होने से अपने कार्यालय में वापस आकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सम्पूर्ण घटनाक्रम बताया। इसके बाद प्रतिवादी बैंक की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। चेक, जो मुखर्जी द्वारा वादी को दिया गया था, भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने पर अनादरित हो गया। इसके बाद वादी बैंक ने मुखर्जी को एक पत्र लिखकर तुरंत ऋण का भुगतान करने की

मांग की और चूक करने पर शेयर बेचने की धमकी दी। मुखर्जी की ओर से कोई उत्तर न आने पर वादी ने इन शेयरों को जालान नामक दलाल के माध्यम से बेच दिया। जालान ने शेयर प्राप्त किए और प्रतिफल का आंशिक भुगतान के लिए वादी को 16,000 रुपये का चेक दिया। हालाँकि, चेक का भुगतान रोक दिया गया और पुलिस, जिसने पहले ही मामला अपने हाथ में ले लिया था, ने शेयरों को अपने कब्जे में ले लिया। चूंकि मुखर्जी का पता नहीं चल सका, इसलिए उनके एक कथित साथी, जिसका नाम शॉ था, के खिलाफ एक आपराधिक मामला शुरू किया गया, लेकिन यह असफल साबित हुआ और शॉ को बरी कर दिया गया। प्रतिवादी बैंक, जिसने भुइया को इन शेयरों की पूरी कीमत चुका दी थी, ने मजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि शेयर, उसके स्वामी होने के आधार पर, उसे वापस कर दिए जाएं। इस आवेदन की जानकारी मिलने पर, वादी बैंक ने वर्तमान वाद दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि शेयरों की गिरवी होने के कारण वादी, कानूनन, उस पर कब्ज़ा करने का हकदार था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, भुइया, जिसे प्रतिवादी बैंक द्वारा भुगतान किया गया था, की मुकदमेबाजी में कोई और दिलचस्पी नहीं थी। इस प्रकार लड़ाई पूरी तरह से दो बैंकों के बीच थी।

यह विवादित नहीं है कि मुखर्जी ने शेयरों पर कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं किया। उनके और भुइया के बीच केवल बैचान के लिए एक करार था और संविदा की शर्तों के तहत शेयरों में संपत्ति तब तक उनके पास नहीं जा सकती थी जब तक कि कीमत का भुगतान नहीं किया जाता। इसलिए, वादी बैंक वास्तविक स्वामी के शेयरों का गिरवीदार नहीं था। इसने अपना दावा पूरी तरह से भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) के प्रावधान पर आधारित किया था, जिसकी भाषा इस प्रकार है:-

"जहां कि कोई व्यक्ति माल का क्रय करके या क्रय करने का करार करके उस माल का या उस माल पर हक के दस्तावेजों पर

कब्जा विक्रेता की सम्मति से या अभिप्राप्त करता है वहां उस व्यक्ति द्वारा या उसके लिए कार्य करने वाले वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा उस माल का या हक के दस्तावेजों का किसी विक्रय, गिरवी या अन्य व्ययन के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को किया परिदान या अंतरण, जो उसे सदभावपूर्वक और माल के बारे में मूल विक्रेता के किसी धारणाधिकार या अन्य अधिकार की सूचना के बिना प्राप्त करता है, ऐसा प्रभाव रखेगा मानो जैसे धारणाधिकार या अधिकार अस्थित्व में था ही नहीं।"

वादी का मामला यह था कि उसने सदभावपूर्वक और मुखर्जी के स्वामित्व में किसी भी दोष की सूचना के बिना गिरवी के माध्यम से शेयर प्राप्त किए थे, जो भुइया से इन शेयरों को खरीदने के लिए सहमत हुए थे और विक्रेता की सहमति से उन पर वास्तविक कब्ज़ा था। नतीजतन, गिरवी माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) के प्रावधान के तहत उसी तरह प्रभावी होगी जैसे कि मूल विक्रेता का अधिकार मौजूद नहीं था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी बैंक का तर्क यह था कि मुखर्जी के पास विक्रेता की सहमति से शेयरों का कब्ज़ा नहीं था और न ही वादी स्वामित्व के दोष की सूचना के बिना वास्तविक गिरवीदार था। इस प्रकार पूरा विवाद इस बिंदु पर केंद्रित है कि क्या साक्ष्य में सामने आए तथ्यों के आधार पर वादी बैंक भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) के प्रावधान का लाभ उठाने का हकदार है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सरकार, जिन्होंने वाद की सुनवाई की, ने वादी के पक्ष में इस प्रश्न का फैसला किया। विद्वान न्यायाधीश की राय थी कि मुखर्जी ने भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) के तहत भुइया या उनके अभिकर्ता, बैंक अधिकारी, की सहमति से शेयरों पर अधिकार प्राप्त किया था और इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए

यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सहमति मुखर्जी की धोखाधड़ी से प्रेरित थी या उनका कार्य अंग्रेजी कानून के अनुसार "चाल से चोरी" का अपराध था। आगे यह पाया गया कि वादी ने स्वामित्व में किसी भी दोष की सूचना के बिना सद्भावना से कार्य किया और इन निष्कर्षों के मद्देनजर विचारण न्यायाधीश ने वादी का वाद डिक्री किया।

इस फैसले के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा एक अपील की गई थी, जिसकी सुनवाई ट्रेवर हैरिस मुख्य न्यायाधीश और बनर्जी न्यायाधीश की पीठ ने की थी। विद्वान न्यायाधीशों ने अपील की अनुमति दी और विचारणीय न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए पलट दिया कि प्रतिवादी के अभिकर्ता ने मुखर्जी को शेयरों के खरीदार के रूप में कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए कभी सहमति नहीं दी थी। शेयरों का प्रतिपादन करने का कोई इरादा ही नहीं था। यह मुखर्जी ही थे जो शेयर लेकर भाग गए और "उनका कृत्य ऐसी चोरी थी मानो उन्होंने उन्हें नीलकृष्ण पॉल की जेब से निकाल लिया हो।" इसी निर्णय के विरुद्ध वादी द्वारा वर्तमान अपील हमारे समक्ष पेश की गई है और विचारणीय बिंदु यह है कि क्या उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है।

श्री मुलिक, जिन्होंने अपीलकर्ता के मामले को सराहनीय निष्पक्षता और दक्षता के साथ प्रस्तुत किया, ने हमारे सामने तर्क दिया है कि इस मामले के तथ्यों पर अपीलीय न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए था कि वादी ने विवादित शेयरों के संबंध में धारा 30 (2) माल विक्रय अधिनियम के प्रावधानानुसार गिरवीदार के अधिकार हासिल कर लिए हैं। उनका कहना है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि वास्तविक स्वामी भुइया और मुखर्जी के बीच इन शेयरों के संबंध में विक्रय की एक वैध संविदा थी और यह कि वादी किसी अन्य के अधिकारों की सूचना के बिना मुखर्जी की ओर से एक वास्तविक गिरवीदार था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा एक तथ्य के रूप में पाया गया है और अपील में इस निष्कर्ष को उलट नहीं किया गया है। वादी को अधिनियम

की धारा 30 (2) का संरक्षण हासिल करने के लिए एकमात्र अन्य चीज यह दिखाना है कि मुखर्जी ने विक्रेता या उसके अभिकर्ता की सहमति से शेयरों पर कब्जा प्राप्त किया है और यह केवल इस बिंदु पर ही नीचे के न्यायालय ने अलग-अलग विचार रखे हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि धारा में प्रयुक्त शब्द "कब्जा" का अर्थ शारीरिक कब्जा के अलावा और कुछ नहीं है और स्वामी की सहमति थी या नहीं, इसका निर्धारण धारा 13 भारतीय संविदा अधिनियम में दी गई "सहमति" की दूसरी परिभाषा के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यदि वास्तव में सहमति थी, तो यह महत्वहीन है कि यह कपट या दुर्व्यपदेशन से प्रेरित थी और इस मामले के निर्धारण में, आपराधिक कानून का कोई सिद्धांत और अंग्रेजी आपराधिक कानून की तकनीकियों को तो बिल्कुल भी आयात नहीं किया जाना चाहिए। तथ्यों पर विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी के अभिकर्ता ने वास्तव में शेयरों के कब्जे को छोड़ने और मुखर्जी को उन्हें लेने की अनुमति देने के लिए सहमति व्यक्त की थी, हालांकि उन्हें मुखर्जी द्वारा दिए गए झूठे वादे से धोखा दिया गया था, जिसे बाद में रखने का उसका इरादा कभी नहीं था।

अधिकांश भाग में, अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए कानून के प्रस्तावों काे प्रतिवादी प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित श्री बनर्जी द्वारा विवादास्पद नहीं किया गया है। उनके बीच विवाद, जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं, मुख्य रूप से इस बिंदु पर है कि क्या मामले के तथ्यों के आधार पर, यह माना जा सकता है कि मुखर्जी को प्रतिवादी के अभिकर्ता की सहमति से शेयरों पर कब्ज़ा मिला। हालाँकि निचले न्यायालयों के निर्णयों में कानून के बिंदुओं पर चर्चा की गई है और विद्वान न्यायाधीशों द्वारा इंग्लैंड में सजातीय क़ानूनों में समान प्रावधानों को लागू करने वाले कई अंग्रेजी मामलों का संदर्भ दिया गया है इसलिए हम संक्षिप्त रूप से अपना विचार व्यक्त करना उचित समझते हैं जिससे माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) में उपयोग किए गए

शब्द "सहमति" के अर्थ और निहितार्थ के संबंध में मौजूद किसी भी संदेह को दूर किया जा सके। दो प्रमुख प्रश्न जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, पहला, क्या माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) के तहत आवश्यक सहमति कपट या दुर्व्यपदेशन से प्रभावित हुए बिना एक स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, और दूसरा, क्या ऐसी सहमति का अस्तित्व, कानून के मामले में, नगण्य हो जाता है यदि धारा में उल्लिखित अपेक्षित विवरण का कोई व्यक्ति चाल या अन्य कपटपूर्ण तरीकों से स्वामी से माल का कब्ज़ा प्राप्त करता है जो उसके कार्य को अपराध के रूप में दंडनीय बनाता है। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा इन बिंदुओं पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है और हमने अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा तय किए गए कई मामलों का उल्लेख किया गया है जहां अंग्रेजी माल विक्रय अधिनियम की धारा 25(2) व कारक अधिनियम की धारा 2(1) के प्रावधानों के संबंध में समान प्रश्न उत्पन्न हुए, जहां वास्तविक स्वामी की सहमति से माल पर कब्ज़ा प्राप्त करने वाले क्रेता या व्यापारिक अभिकर्ता द्वारा किए गए स्वभाव के संदर्भ में लगभग एक ही भाषा का उपयोग किया गया है। हमारे उद्देश्य के लिए हमारे सामने उद्धृत अंग्रेजी मामलों की चर्चा करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है। हम केवल, जहां आवश्यक हो, उन प्रमुख सिद्धांतों की जांच करेंगे जिन पर अंग्रेजी न्यायाधीशों की प्रमुख फैसले आधारित होने का दावा करती हैं और देखेंगे कि क्या वे उन प्रश्नों पर कोई प्रकाश डालते हैं जिन पर इस मामले में विचार करने की आवश्यकता है।

हम दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण से सहमत हैं कि माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) में प्रयुक्त शब्द "सम्मति" का अर्थ है "एक ही बात पर एक ही भावना से सहमत होना" जैसा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित किया गया है। माल विक्रय अधिनियम में "सम्मति" की कोई परिभाषा नहीं है लेकिन अधिनियम की धारा 2(15) निश्चित रूप से बताती है कि अधिनियम में प्रयुक्त और

परिभाषित नहीं किए गए अभिव्यक्ति वही समान अर्थ रखेंगे जो भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित है। संविदा अधिनियम की धारा 14 अभिव्यक्ति "स्वतंत्र सम्मति" को परिभाषित करती है और सममति तब स्वतंत्र होती है जब यह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट या दुर्व्यपदेशन के कारण नहीं होती है। गलत प्रतिनिधित्व से प्रेरित सम्मति स्वतंत्र नहीं हो सकती है लेकिन फिर भी यह वास्तविक हो सकती है और 'आमतौर पर कपट या असम्यक असर का प्रभाव केवल करार को शून्यकरणीय करना होता है, शून्य नहीं। यदि कोई निर्दोष क्रेता या गिरवीदार उस व्यक्ति से माल प्राप्त करता है जिसके पास उसका कब्जा है, जिसका कब्जे का अधिकार कपट के आधार पर रद्द करने योग्य है लेकिन लेनदेन के समय वास्तव में रद्द नहीं हुआ था, तो कोई कारण नहीं है कि ऐसे निर्दोष क्रेता या गिरवीदार के अधिकारों की रक्षा नहीं की जानी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में स्वामी या जमानतदार का अधिकार बिना संदेह निश्चित किए जाने योग्य है लेकिन जब तक यह निर्धारित नहीं होता है तब तक यह उसे बिना सूचना के किसी निर्दोष अंतरिती के पक्ष में अधिकार उत्पन्न करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है। यह प्रस्ताव अंग्रेजी कानून में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और हमें लगता है कि यह सिद्धांत पर अच्छी तरह से स्थापित है। काह्न बनाम पॉकेट्स ब्रिस्टल चैनल स्टीम पैकेट कंपनी**(1)** में, कोलिन्स एलजे ने निम्नलिखित उद्धृत अभिनिर्धारण किया:-

"कब्जा प्राप्त करने में वास्तविक कब्जे में रहने वाला व्यक्ति कितना भी कपटी क्यों न हो, बशर्ते कि यह चालाकी से की गई चोरी न हो, चाहे वह अपने ऊपर जताए गए भरोसे का कितना ही दुरुपयोग क्यों न कर ले या उस आदेश का उल्लंघन न कर दे जिसके तहत उसे कब्ज़ा मिला है, वह अपने प्रकृति से क्रेता को एक अच्छा अधिकार दे सकता है।"

तथाकथित अपवाद के संबंध में विद्वान न्यायाधीश की राय जहां "चाल से चोरी" हुई है, बाद के मामलों में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की टिप्पणियों का विषय रही है, जैसा कि हम वर्तमान में देखेंगे, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित मुख्य प्रस्ताव पर कभी विवाद नहीं हुआ**(2)**। इस बिंदु पर कानून को पियर्सन बनाम रोज़**(3)** में डेनिंग एलजे द्वारा इस प्रकार सारांशित किया गया है:

> "कपट का प्रभाव.....एक नियम के रूप में केवल लेन-देन को शून्यकरणीय बनाता है, शून्य नहीं और यदि एक निर्दोष क्रेता ने लेन-देन को शून्य करने से पहले माल खरीदा है तो वास्तविक क्रेता उन पर वापस दावा नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारिक अभिकर्ता झूठी दिखावे, जैसे कि उसे एक बेकार चेक देकर संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या झूठा दिखावा करके स्वामी को प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए संपत्ति उसे सौंपने के लिए प्रेरित करता है, जबकि वह बड़े पैमाने पर व्यवसाय में नहीं था तो स्वामी उस निर्दोष क्रेता से माल वापस नहीं मांग सकता, जिसने उसे अच्छे विश्वास के साथ व्यापारिक अभिकर्ता से खरीदा हो..... हो सकता है कि सहमति कपट से प्राप्त की गई हो लेकिन जब तक उसे टाला नहीं जाता, यह एक सहमति है जो कारक अधिनियम को संचालित करने में सक्षम बनाती है।"

इस प्रकार झूठे बहाने से माल का कब्ज़ा प्राप्त करना इंग्लैंड में कारक अधिनियम के संचालन को बाहर नहीं करता है और हमारी राय में यह भारत में माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) के संचालन को भी बाहर नहीं करता है। हालाँकि, स्थिति पूरी तरह से अलग है यदि किया गया कपट इस प्रकार का है जो किसी विशेष व्यक्ति को माल का कब्ज़ा देने के लिए स्वामी की ओर से सहमति देने से रोकती है। इस

प्रकार ए खुद को बी होने का झूठा प्रतिनिधित्व करके स्वामी से माल का कब्ज़ा प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामलों में स्वामी कभी भी ए द्वारा माल के कब्जे के लिए सहमति नहीं दे सकता है; तथाकथित सहमति का वास्तविक सहमति न होना कानून में पूरी तरह से अमान्य बात है। लेक बनाम सिमंस (4) में लॉर्ड हाल्डेन ने एक समान बिंदु से निपटने के दौरान निम्नलिखित टिप्पणियां की "अपीलकर्ता ने सोचा कि वह एक अलग व्यक्ति, वान डेर बोर्ग की पत्नी के साथ काम कर रहा था, और केवल इसी आधार पर उसने माल नहीं दिया। उसने कभी भी उस महिला के साथ संविदा करने का इरादा नहीं किया था। उसने जानबूझकर कपट और चाल से कब्ज़ा हासिल कर लिया। विक्रेता के साथ उसके मन की बिल्कुल भी सहमति नहीं थी जो किसी भी संविदात्मक अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक थी। बाद वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की पहचान के बारे में पूरी तरह से धोखा दिया गया जिसके साथ वह लेनदेन कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में, मुझे लगता है कि कोई आम सहमति नहीं थी।"

इसलिए, स्थिति यह है कि जब कब्जे का हस्तांतरण केवल कपट से प्रेरित होने के कारण शून्यकरणीय है, जिसे स्वामी के विकल्प पर रद्द किया जा सकता है, तो गलत प्रतिनिधित्व के बाद की गई सहमति माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) के अर्थ के भीतर पर्याप्त सहमति है। लेकिन जहां कपट से उस व्यक्ति की पहचान या संपत्ति जिसके संबंध में कब्ज़ा दिया गया था, के संबंध में कोई त्रुटि उत्पन्न हुई तो पूरी चीज़ शून्य है "एक ही बात पर एक ही भावना से सहमत होना" नहीं है। दूसरा प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुप्रयोग में कोई अंतर आएगा यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वामी से माल का कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए किया गया धोखा इस प्रकार का है कि उसे आपराधिक कृत्य का दोषी बना दिया जाए? ऊपर जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, इस प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, यदि यह तथ्य न हो कि अंग्रेजी आपराधिक कानून के कुछ

तकनीकी नियमों के कारण विषय में जटिलता हो गई है। यह याद रखना चाहिए कि माल विक्रय अधिनियम की धारा 30(2) में यह प्रावधान है कि क्रेता, जिसे बेचे गए माल में संपत्ति अभी तक पारित नहीं हुई है, को विक्रेता की सहमति से माल का कब्ज़ा प्राप्त करना होगा, इससे पहले कि वह किसी निर्दोष क्रेता या गिरवीदार को स्वामित्व दे सके। इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि माल के स्वामी की सहमति स्थापित करने के लिए उसकी मन:स्थिति ही विचार के लिए एकमात्र आवश्यकता है न कि माल प्राप्त करने वाले की। भले ही स्वामी को कपटपूर्ण दुर्व्यपदेशन द्वारा माल छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया हो, फिर भी यह माना जाना चाहिए कि उसने कब्ज़ा देने के लिए सहमति दी है; और यह तथ्य कि प्राप्तकर्ता के पास माल चुराने या उसका दुरुपयोग करने का बेईमान इरादा या पूर्व-संयोजित योजना थी और वास्तव में उनका दुरुपयोग किया गया था तो उसे आपराधिक अपराध के लिए उत्तरदायी बना सकता है, लेकिन वास्तव में दी गई स्वामी की सहमति को रद्द नहीं किया जा सकता है। माल के कपटी प्राप्तकर्ता को आपराधिक रूप से दंडित करने के लिए, वास्तविक बात उसका बेईमान इरादा है लेकिन जैसा कि बैंक्स एलजे ने फोल्क्स बनाम किंग(5) में कहा था कि कारक अधिनियम के तहत माल के स्वामी द्वारा दी गई सम्मति यह निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा, "दोनों विचारों को पूरी तरह से अलग रखा जाना चाहिए। एक को दूसरे के विचार से पराजित करने की अनुमति देना मेरी राय में उस सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण हिस्से को समाप्त करना है जिसका उद्देश्य कारण अधिनियम द्वारा प्रदान करने का था। "हमारी राय में, यही आवश्यक विश्लेषण माल विक्रय अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में भी लागू होता है।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अंग्रेजी कारक अधिनियम के प्रयोजन के लिए झूठे बहाने से माल प्राप्त करना स्वामी की नकारात्मक सहमति नहीं है। यहां तक कि जमानतदार द्वारा की गई चोरी भी अंग्रेजी निर्णयों के अनुसार सहमति को बाहर नहीं

करती है। इसका मतलब यह है कि यदि स्वामी किसी अभिकर्ता को अपना सामान किराये पर या मरम्मत के लिए रखने की अनुमति देता है और अभिकर्ता बाद में उन्हें चुराने या दुरुपयोग करने और उन्हें दूसरे को बेचने का मन बनाता है तो अभिकर्ता जमानतदार के रूप में चोरी का दोषी हो सकता है लेकिन उसके कब्जे के लिए स्वामी की सहमति इससे प्रभावित नहीं हो सकती। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी कानून में जमानतदार द्वारा चोरी और चाल से चोरी के बीच अंतर किया गया है और यदि ऊपर दिए गए उदाहरण में अभिकर्ता ने बाद में माल चुराने का मन बनाने के बजाय कब्ज़ा प्राप्त करते समय शुरुआत में ही बेईमानी का इरादा किया था तो वह "चाल से चोरी" का दोषी है और कानून के अनुसार कब्जा स्वामी के पास रहता है और उसे स्वामी की सहमति के बिना "लेने वाला" माना जाता है। इसमें स्पष्ट रूप से एक कानूनी कल्पना शामिल है, हालांकि माल वास्तव में स्वामी द्वारा आरोपी व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, फिर भी उस व्यक्ति द्वारा की गई चाल के कारण स्वामी को अभी भी माल का कब्ज़ा जारी रखना होता है और आरोपी को स्वामी की इच्छा के विरुद्ध माल पर कब्ज़ा करने के लिए चोरी का दोषी माना जाता है। । आमतौर पर, अंग्रेजी कानून के अनुसार, चाल से चोरी का अपराध दो तरह से किया जा सकता है: पहला, जहां माल का स्वामी, चाल से प्रेरित होकर, आरोपी के पक्ष में माल का कब्जा स्वेच्छा से छोड़ देता है लेकिन उसका उक्त संपत्ति हस्तांतरित करने का इरादा नहीं है और प्राप्तकर्ता के पास *एनिमस फुरांडी* है। दूसरे, जब आरोपी खुद को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करके या स्वामी को यह सोचकर कपट करता है कि वह अलग-अलग माल वितरित कर रहा है, माल पर कब्ज़ा करने का प्रयास करता है (6)। मामलों की दूसरी श्रेणी में, स्वामी की ओर से कोई वास्तविक सहमति नहीं होती है और जब इस प्रकार की चाल से चोरी की जाती है तो इंग्लैंड में कारक अधिनियम के संचालन को बाहर

रखा जाता है। भारतीय कानून के तहत स्थिति ऊपर बताए गए सिद्धांतों के अनुसार समान है।

हालाँकि, मामलों की पहली श्रेणी के संबंध में, अंग्रेजी अदालतों के फैसले बिल्कुल एक समान नहीं हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, काह्न बनाम पॉकेट्स ब्रिस्टल चैनल इत्यादि (7) में कोलिन्स जे. ने टिप्पणी की थी कि "वास्तविक कब्जे में रहने वाला व्यक्ति कब्ज़ा प्राप्त करने में कितना भी कपटी क्यों न हो, वह अपने प्रकृत्ति से एक अच्छा स्वामित्व दे सकता है बशर्ते कि यह चाल से की गई चोरी न हो।" चाल से चोरी के मामले में अपवाद के संबंध में, हालांकि यह एक ओबिटर से अधिक नहीं हो सकता है, ओपेनहाइमर बनाम फ्रेज़र (8) में इंग्लैंड में अपील की अदालत द्वारा अच्छे कानून के रूप में स्वीकार किया गया था। दूसरी ओर फोल्क्स बनाम किंग(9) में बैंक्स एलजे और स्क्रूटन एलजे द्वारा यह माना गया था कि जब सहमति वास्तव में माल के स्वामी द्वारा दी गई थी तो यह महत्वहीन था कि प्राप्तकर्ता चाल से चोरी का दोषी था और इस दृष्टिकोण को लेक बनाम सिमंस (10) में अपीलीय न्यायालय के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया था, हालांकि एटकिन एलजे ने एक असहमतिपूर्ण निर्णय दिया था। लेक बनाम सिमंस (11) में निर्णय हाउस ऑफ लॉर्ड्स (12) द्वारा उलट दिया गया था लेकिन उनका आधिपत्य आपराधिक कानून के किसी तकनीकी सिद्धांत पर नहीं बल्कि व्यापक आधार पर आगे बढ़ा, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक गलती थी जो सहमति देने वाले दिमाग के लिए घातक थी। फोल्क्स बनाम किंग(13) में लिए गए दृष्टिकोण को पियर्सन बनाम रोज़(14) के हालिया निर्णय में अनुमोदित किया गया है। इस प्रकार, लॉर्ड सुमनेर की भाषा को उद्धृत करने के लिए "इस बिंदु पर आधिकारिक राय का एक सांकेतिक और अनिर्णायक संघर्ष है" (15)। हमारी राय में फोल्क्स बनाम किंग(16) में लिया गया दृष्टिकोण ही उचित दृष्टिकोण है; और यदि, जैसा कि स्क्रूटन एलजे ने उस मामले में कहा था, संसद संभवतः कारक अधिनियम द्वारा शासित

वाणिज्यिक लेनदेन में आपराधिक कानून के कृत्रिम भेदों को लागू करने का इरादा नहीं कर सकती है, तो अंग्रेजी आपराधिक कानून का अत्यधिक तकनीकी नियम, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी न्यायाधीशों द्वारा एक चोर को दंडित करने के लिए तैयार की गई कानूनी कल्पना में हुई थी, जो अन्यथा भारतीय माल विक्रय अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि से बच जाता, को आयात करने का औचित्य अभी भी कम है। सहमति है या नहीं, इसे संविदा के कानून के सिद्धांतों के अनुसार एक तथ्य के रूप में साबित किया जाना चाहिए और जब यह साबित हो जाता है, यह अस्तित्व में है तो इसके अस्तित्व को आपराधिक कानून के किसी भी नियम को लागू कर रद्द नहीं किया जा सकता है।

इन सिद्धांतों के आलोक में हम अब इस मामले के तथ्यों की जांच के लिए आगे बढ़ेंगे। पूरा सवाल यह है कि क्या मुखर्जी को विक्रेता की सहमति से शेयरों पर कब्ज़ा मिला और यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी के क्लर्क की सहमति, जो स्वामी के अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था, की सहमति स्वामी स्वयं के समान प्रभावी होगी।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, भुइया ने 14 फरवरी, 1946 को प्रतिवादी बैंक को शेयर भेजे। उस तारीख को उनके द्वारा प्रतिवादी को लिखा गया पत्र इस प्रकार समाप्त होता है:

> "यदि आप श्री डीएन मुखर्जी से संलग्न बिल के अनुसार 38,562.80 रुपये की राशि वसूल कर लें और शेयर उन्हें सौंप दें तथा प्राप्त राशि मेरे खाता नंबर 1 में जमा कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। "

अगले दिन, यानी 15 तारीख को, भुइया ने मुखर्जी को पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्होंने यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक की बड़ाबाजार शाखा में 300 आयरन और 500 स्टील कॉर्पोरेशन के शेयर जमा किए हैं और तुरंत भुगतान के विरुद्ध मुखर्जी से

शेयरों की डिलीवरी लेने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद 18 फरवरी को, प्रतिवादी बैंक के नकदी विभाग के एक पुराने कर्मचारी, नीलकृष्ण पॉल को मुख्य खजांची द्वारा मुखर्जी से पैसे प्राप्त करने और शेयर सौंपने के उद्देश्य से उनके कार्यालय में मिलने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी के एक अधिकारी सचिन्द्र सेन, जिनकी सलाह पर पॉल को मुखर्जी के पास भेजा गया था, अपने बयान में कहते हैं कि उन्होंने पॉल को निश्चित रूप से निर्देश दिया था कि जब तक उन्हें भुगतान नहीं मिल जाता, तब तक शेयर हस्तांतरित न करें। भुगतान के तरीके के संबंध में, सेन का कहना है कि उनके और मुखर्जी के बीच यह पहले से ही तय था कि नकद में पैसे का भुगतान करने के बजाय, वह प्रतिवादी बैंक को पंजाब नेशनल बैंक, जहां उनका खाता है, का भुगतान आदेश देंगे। सेन ने पॉल से कहा कि वह भुगतान आदेश की सावधानीपूर्वक जांच करे और शेयरों को तभी हस्तांतरित करे जब वह इसके बारे में संतुष्ट हो; अन्यथा उसे शेयरों के साथ कार्यालय वापस आना चाहिए। पॉल, जो प्रतिवादी की ओर से मुख्य गवाह है, अपने बयान में कहता है कि उसे जो निर्देश मिला था वह भुगतान आदेश प्राप्त करने के बाद शेयरों को वितरित करना था। 18 तारीख को लगभग 11 बजे पॉल ने मुखर्जी को उनके कार्यालय कक्ष में देखा और जब उन्होंने मुखर्जी को बताया कि वह यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक से शेयर सौंपने आए हैं, तो मुखर्जी ने उन्हें सीट पर बैठने के लिए कहा। इसके बाद मुखर्जी ने शेयर मांगे। पॉल ने उससे कहा कि जब तक उसे भुगतान आदेश नहीं दिया जाता वह शेयर हस्तांतरित नहीं कर सकता। मुखर्जी ने तब कहा, "मैं केवल शेयरों और कागजात पर एक नजर डालना चाहता हूं, यह देखने के लिए कि वे ठीक हैं या नहीं।" इस पर पॉल ने शेयरों को मेज पर रख दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसका वर्णन उन्होंने अपने बयान में इस प्रकार किया है:-

> "तब वह एक के बाद एक शेयरों को देख रहे थे। जब मुखर्जी चैंबर छोड़ने वाले थे तो मैंने उनसे कहा कि वह दूर न जाएं बल्कि

मुझे भुगतान आदेश दे दें। उन्होंने मुझसे कहा, 'मैं भुगतान आदेश लेने के लिए बाहर जा रहा हूं,' 'यह तैयार है, आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, मैं आ रहा हूं।' फिर वह कक्ष से बाहर चले गये."

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब पॉल ने शेयर प्रमाणपत्र मेज पर रखे और मुखर्जी को उनकी जांच करने की अनुमति दी तो उन्होंने शेयरों पर कब्ज़ा या नियंत्रण नहीं छोड़ा। यह सत्य है कि मुखर्जी ने कागजात संभाले लेकिन उन्होंने ऐसा पॉल की उपस्थिति में किया, जो उसी मेज के सामने उनके पास में बैठे थे। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि कागजात की जांच के लिए मुखर्जी के पास न्यूनतम शारीरिक कब्ज़ा था। जब मुखर्जी शेयर हाथ में लेकर कमरे से बाहर निकले तो निस्संदेह शेयरों पर उनका कब्ज़ा हो गया; लेकिन रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर, हमें यह मानना संभव नहीं लगता कि उसे पॉल की सहमति से कब्ज़ा मिला है। साक्ष्य से पता चलता है कि पॉल ने वास्तव में बिना कोई भुगतान किए शेयर लेकर जाने का विरोध किया और आपत्ति जताई थी यह सत्य है कि मुखर्जी ने पॉल से कहा था कि वह भुगतान आदेश प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहा है और तुरंत वापस आ जाएगा; लेकिन हम श्री मुलिक से सहमत नहीं हो सकते कि पॉल ने भुगतान आदेश के साथ वापस आने के मुखर्जी के वादे पर भरोसा करते हुए कागजात वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। मुखर्जी ने पॉल को इस मामले में अपनी सहमति या असहमति जताने का कोई मौका नहीं दिया। पॉल के विरोध के बावजूद पॉल को इंतजार करने के लिए कहकर वह कागजात लेकर चला गया। पॉल ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने 2 या 3 मिनट तक इंतजार किया और जब मुखर्जी वापस नहीं आए तो वह चिंतित हो गए और कार्यालय से बाहर काउंटर की ओर गए, जहां उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे मिले। व्यक्ति ने उन्हें बताया कि मुखर्जी कार्यालय में कहीं नहीं हैं। इससे पता चलता है कि पॉल ने वास्तव में मुखर्जी के आश्वासन पर भरोसा नहीं किया और उस आश्वासन

पर मुखर्जी को शेयरों पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दी। यह उनकी स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध था कि मुखर्जी ने शेयर ले लिए और उनके साथ चैंबर छोड़ दिया और उन्हें एक या दो मिनट तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि वह उस समय कोई अन्य विकल्प नहीं सोच सकते थे। समग्र साक्ष्यों को देखते हुए, हम सोचते हैं कि उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ का निर्णय सही है और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि मुखर्जी को पॉल की सहमति से शेयरों पर कब्ज़ा मिला। इसलिए, परिणाम यह है कि अपील खारिज की जाती है और अपीलीय न्यायालय के फैसले की पुष्टि की जाती है। चूँकि वादी और प्रतिवादी दोनों निर्दोष व्यक्ति थे, जो किसी तीसरे पक्ष के कपट के कारण पीड़ित हुए, हम निर्देश देते हैं कि दोनों पक्ष सभी न्यायालय में अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

अपील खारिज की जाती है।

अपीलकर्ता के लिए अभिकर्ता: सुकुमार घोष।

प्रतिवादी के लिए अभिकर्ता: बीएन घोष।

01. [1899] 01 क्यूबी 643, 659 पर।

02. एलजे स्कूटन द्वारा उल्लेखित फोक्स बनाम किंग [1923] 01 केबी 282, 301 पर।

03. [1950] 02 ऑल ईआर 1027, 1032 पर।

04. [1923] 01 केबी 282, 297 पर।

05. [1923] 01 केबी 282, 297 पर।

06. वाईट होर्सन बनाम डेविसन [1911] 01 केबी 463, 479।

07. [1899] 01 क्यूबी 643, 659 पर।

08. [1907] 02 केबी 50।

09. [1923] 01 केबी 282।

10. [1926] 02 केबी 51।

11. [1926] 02 केबी 51।

12. [1927] एबी 487।

13. [1923] 01 केबी 282।

14. [1950] 02 ऑल ईआर 1027।

15. [1923] 01 केबी 282।

16. लेक बनाम सिमंस [1927] एसी 487, 510 देखिए।

यह अनुवाद आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादन न्यायिक अधिकारी रिछपाल सिंह गिला (आरजेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण :- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वय के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।